राजस्थान में सहकारी बुनकर समितियां

1729. डा० अबरार अहमद : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितनी सहकारी बुनकर समितियां हैं ;

(ख) कितनी समितियां कार्य कर रही हैं और कितनी बंद पड़ी हैं तथा कितनी समितियों को धागा उपलब्ध कराया जा रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसे बुनकरों को, जिन्हें राजस्थान के उद्योग विभाग द्वारा ऋण दिया गया था, परेशान किया जा रहा है;

(घ) गुजराती समाज बुनकर सहकारी समिति को कुल कितना ऋण दिया गया है और उक्त समिति ने किस-किस तिथि पर ऋण की किश्तों का भुगतान किया है तथा उसे दिये गये ऋण की मूल राशि, उस पर देय ब्याज और भुगतान के लिये शेष राशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) बकाया राशि के भुगतान के लिये पिछले चौदह वर्षों के दौरान उन्हें कितनी बार लिखित नोटिस जारी किये गये थे ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) भारत सरकार के पास प्राप्त अंतिम रिपोर्ट के अनुसार इस समय राजस्थान में 638 बुनकर सहकारी समितियां हैं ।

(ख) इनमें से 231 समितियां कार्य कर रही हैं और 407 बंद पड़ी हैं । 231 समितियों को धागा उपलब्ध कराया जा रहा हैं ।

(ग) केंद्र सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं हैं ।

(घ) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में गुजराती समाज बुनकर सहकारी समिति नाम की कोई समिति नहीं हैं । तथापि राज्य सरकार ने सूचित किया हैं कि मै० गुजराती मोमिन सहकारी समिति लि०, सवाई माधोपुर को 1-4-1960 को 39,375 - रुपये का ऋण दिया गया था । 31-3-1990 की स्थिति के अनुसार 18,160 - मूल राशि और 39,954 - रुपये ब्याज के रूप में देने शेष हैं ।

(ङ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मूल राशि व ब्याज बकाया राशि देने के लिए इस उक्त समिति को तेरह नोटिस दिये गये थे नोटिस जिला उद्योग केंद्र और सहकारी विभाग, सवाई माधोपुर द्वारा दिये गये । यह उक्त समिति पर समाप्ति पर हैं ।

Closure of Azamjahi Textile Mills in Warangal district in Andhra Pradesh

1730. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal to close Azamjahi Textile Mills in Warangal district in Andhra Pradesh; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT) (a) and (b) In order to improve the performance of National Textile Corporation mills, including Azamjahi Mills, various alternatives are under consideration of the Government as a long term solution. However, no decision has been taken in this regard.

Modification of the Jute reservation orders

1731. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 113 given in the Rajya Sabha on 16th July, 1991 and state:

(a) whether Government plan to continue with the Jute (Packaging)